International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 17-12-2020; Accepted: 01-01-2021; Published: 23-01-2021
www.educationjournal.org
Volume 6; Issue 1; 2021; Page No. 26-29

कोविड–19 महामारी का भारतीय राजनीति एवं शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव

आदित्य कुमार
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
कोविड–19 महामारी अर्थात् कोरोना वायरस के प्रभाव से आज मानव सभ्यता का कोई भी भाग अछूता नहीं है। कोविड–19 महामारी के दौर में समूचा विश्व अलग–अलग पतवारों में सवार समुद्र की एक दिशा–विहीन लहर में भटक रहा है। इस महामारी का सर्वाधिक प्रभाव भारत के साथ–साथ समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। महामारी के कारण उत्पादन की रफ्तार एवं स्तर कम हो गया है, व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला अत्यधिक प्रभावित हुई है, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमाण्ड–सप्लाई चैन प्रभावित हुई है जबकि विमानन, होटल, आतिथ्य, पर्यटन एवं पर्यटन बाजार आदि व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। किन्तु भारतीय राजनीति एवं शिक्षा व्यवस्था पर इस महामारी से पड़ने वाले प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में, जहाँ एक तरफ कोविड–19 का प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा है, निरन्तर नये मामले उभर कर सामने आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के साथ–साथ पंचायती राज संस्थायें भी इस महामारी से निपटने की प्रक्रिया में जी जान से जुटी हैं, जिसके अन्तर्गत हमें भारतीय राजनीति में एक विशेष प्रकार के 'सहकार', 'सहयोगात्मक' एवं 'सहकारी संघवाद' की झलक मिलती है।

मूल शब्दः कोविड–19, भारत, शिक्षा, सहकारी संघवाद, राजनीतिक व्यवस्था आदि।

प्रस्तावना
कोविड–19 महामारी ने सम्पूर्ण विश्व व्यवस्था को प्रभावित किया है, आज विभिन्न बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सकल घरेलू उत्पाद गिर गया है। पर्यटन, आवागमन, व्यापार व सेवा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुये हैं, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में 2 महीने से अधिक समय के लॉकडाउन के उपरान्त इस महामारी का सर्वाधिक दंश हमारी अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है किन्तु कोई ऐसा क्षेत्र अथवा कार्य नहीं है जो महामारी के प्रभाव से खुद को पृथक रख सकने में समर्थ हो। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ–साथ वैश्विक आर्थिक मंदी के इस कठिन दौर में कोविड–19 महामारी के प्रभाव से भारतीय राजनीति एवं शिक्षा व्यवस्था भी अछूती नहीं रह सकती है। आज कोविड–19 महामारी न केवल व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य सम्बन्ध बल्कि व्यक्ति का राज्य के साथ सम्बन्ध निर्धारित करने का महत्वपूर्ण कारण बन गई है। सम्बद्ध लेख में कोविड–19 महामारी के प्रभाव का मुख्य रूप से इन्हीं दो पक्षों (भारतीय राजनीति एवं शिक्षा व्यवस्था) पर केन्द्रित अध्ययन करेंगे।

(क) भारतीय राजनीति पर प्रभावः ज्ञातव्य है कि मानव सभ्यता के इतिहास में महामारियों का आना तथा राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव कोई नवीन घटना नही है। इससे पूर्व भी सन् 1918 में आई 'स्पेनिश फ्लू' महामारी कम विनाशकारी नहीं थी। 'स्पेनिश फ्लू' महामारी की भयंकर त्रासदी (जिसमें अकेले भारत में लगभग 1.8 करोड़ लोगों की जानें गयी थी) के उपरान्त भारतीय जनमानस महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वराज प्रप्ति हेतु आन्दोलन की ओर उद्वेलित हो उठा था। इसे चाहे संयोग कहें अथवा कोविड–19 महामारी का प्रभाव कि प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक आवाहन पर सम्पूर्ण भारतीय जनमानस एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा रहा। मगर कोविड–19 महामारी के प्रभाव के फलस्वरुप निकट भविष्य में भारतीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन देखें जा सकते हैं, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के रूप में देख सकते हैंः–

- सहकारी संघवाद, कोविड–19 महामारी का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संघीय व्यवस्था पर पड़ा है। इस महामारी के दौर में स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पाँच–पाँच बार घण्टों बातचीत अथवा ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से कांफ्रेंस किया जाना, साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा राज्यों के संदर्भ में 'स्टेट फ्रन्टलाइन वारियर्स' शब्द का प्रयोग किया जाना भारतीय संघीय व्यवस्था को 'सहकारी संघवाद' के रुप में अधिक समृद्ध करता है। इतना ही नहीं कुछ अपवादों विशेषतः दिल्ली एवं हरियाणा राज्य में महामारी के दौर में प्रतिदिन होने वाले कर्मचारियों के प्रवासन पर उत्पन्न असहमति को छोड़ दें तो न केवल एक समान राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्य बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में भी एक सहकार एवं समन्वय दिखाई देता है। यह इस महामारी के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था एक 'सहयोगात्मक एवं सहकारी संघवाद' एवं 'टीम वर्क' की भावना की और दृढ़ता से अग्रसर होता दिखाई दे रही है।
- मजबूत होता प्रधानमंत्री कार्यालय– कोविड–19 महामारी के प्रभाव में PMO (Prime Minister's Office) अर्थात् प्रधानमंत्री कार्यालय आज एक बार फिर अपने सर्वाधिक मजबूत स्थिति में है। सन् 1947 में स्थापित 'प्रधानमंत्री सचिवालय' (जिसे सन् 1977 में 'प्रधानमंत्री कार्यालय' के रुप में परिवर्तित किया गया) प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के उपरान्त विभिन्न उतार–चढ़ाव के बाद एक बार फिर अधिक मजबूत स्थिति में हैं। आज सभी निर्णयों के केन्द्र स्वयं प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय ही दिखाई दे रहा है। कमोबेश यही स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की है।
- भारतीय चुनावों में चाहे वे राज्य विधानसभा के चुनाव हों अथवा फिर लोकसभा के चुनाव कहीं और कभी भी 'स्वास्थ्य सेवाओं' को प्रमुख चुनावी मुद्दे के रुप में नहीं रखा जाता रहा। कदाचित् स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख सेवायें प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दी गयी थी किन्तु इस कोविड–19 महामारी से निपटने की प्रक्रिया में निजी स्वास्थ्य केन्द्रों की अत्यन्त सीमित भूमिका को देखते हुये यह सम्भव है कि आने वाले

समय में 'स्वास्थ्य सम्बंधी मुद्दे' प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे।

कोविड–19 महामारी के प्रभाव में चुनावों से जुड़ा एक और परिवर्तन देखने को मिल सकता है क्योंकि जल्द ही बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं जिसमें यह बात उभर कर सामने आई है कि यह चुनाव ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पन्न कराये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्न यह है कि क्या निकट भविष्य में उत्तर–प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के साथ–साथ अन्य विधानसभाओं के चुनाव हेतु किस माध्यम का प्रयोग किया जाएगा। फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि निकट भविष्य में हम चुनावी प्रक्रिया के एक नये युग में प्रवेश करने जा रहे हैं।

- कोविड–19 के सन्दर्भ में चाहे सार्क (SAARC- South Asian Association for Regional Cooperation) देशों को एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रश्न हो या फिर अन्य देशों को मेडिकल सुविधा, विशेषतः दवायें उपलब्ध कराने की बात हो दोनों में ही प्रधानमंत्री जी एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। प्रारम्भ में कोविड–19 महामारी से निबटने हेतु सार्क देशों का ऑनलाइन सम्मेलन/वर्चुअल कांफ्रेंस बुलाने तथा 'साझा फण्ड' एकत्रित किये जाने में प्रधानमंत्री जी की अग्रणी भूमिका रही है। महत्वपूर्ण यह है कि वीडियो कॉफ्रेंस/वर्चुअल कांफ्रेंस में पाकिस्तान सहित सभी सार्क देशों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। यह तब हुआ जब पिछले चार वर्षों (सन् 2016 से ही) भारत एवं पाकिस्तान के मध्य मतभेद के चलते सार्क देशों में निरन्तर गतिरोध जारी था। वहीं मेडिकल सेवाओं विशेषतः दवायें उपलब्ध कराये जाने की बात करें (जिसे प्रायः मेडिकल डिप्लोमेसी के रूप में भी देखा जा रहा है) तो सार्क देशों के साथ–साथ अमरीका, ब्राजील व इज़राइल सहित अन्य विभिन्न देशों को मलेरिया रोधी दवा 'हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन' उपलब्ध कराके अपनी मेडिकल डिप्लोमेसी को और अधिक सुदृढ़ किया है।
- लम्बे समय तक रहे लॉकडाउन के उपरान्त मन्द पड़ी आर्थिक विकास प्रक्रिया व आर्थिक क्रियाकलापों को पटरी पर लाने हेतु भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा के साथ–साथ आत्मनिर्भर बनने व स्थानीय ब्रांड के उपयोग पर बल दिया गया। प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार उपलब्ध कराए जाने के साथ–साथ मनरेगा हेतु भारत सरकार द्वारा 40000 करोड रुपए (20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में से) का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। निसंदेह भारत सरकार के ये कदम आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं किन्तु आने वाला समय अत्यंत संवेदनशील व अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, ऐसे में किसी भी विषय पर एक निश्चित अनुमान लगाया जाना कठिन है। यह सब कुछ मानव सभ्यता के समक्ष उत्पन्न संकट के प्रभाव एवं उसके समाधान तथा इस आपात स्थिति से निकलने में सरकार की भूमिका एवं उसकी नीतिगत निर्णय आदि पर निर्भर करेगा।

(ख) भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रभावः कोविड–19 महामारी ने न केवल स्कूली शिक्षा, शिक्षक एवं छात्र तथा नीति निर्माताओं को प्रभावित किया है बल्कि समूची शिक्षा व्यवस्था को ही प्रभावित किया है। आज ग्राम पंचायतों में स्थापित प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक 'क्लासरूम माध्यम' से शिक्षण कार्य ठप पड़े हैं, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गरीब, पिछड़े व वंचित वर्ग के छात्रों के साथ–साथ प्रवासी छात्रों (विशेषतः ऐसे छात्र जो ग्रामीण व पिछड़े इलाकों से निकलकर प्रयागराज, दिल्ली, कोटा आदि जैसे शहरों में किराये के कमरें में रहकर शिक्षा अर्जित करते हैं) पर पड़ा है। निःसंदेह यह एक ऐसी संस्थात्मक डिस्कूलिंग की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से दूरस्थ शिक्षा व 'ऑनलाइन शिक्षा' को प्रोत्साहित किया जा रहा है जबकि यह सर्वविदित है कि न केवल 'प्राइमरी व जूनियर' स्तर के छात्र एवं शिक्षक बल्कि अनेक विश्वविद्यालयों के शिक्षक व छात्र इन ऑनलाइन माध्यमों द्वारा अध्ययन व अध्यापन की प्रक्रिया से अपरिचित एवं असहज हैं। ऐसी स्थिति में 'दूरस्थ शिक्षा' व 'ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया' कितनी कारगर सिद्ध होती है यह देखने योग्य होगा। इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पहल सराहनीय है। कोविड–19 महामारी का भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से देखा जा सकता हैः–

निःसंदेह वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण एवं आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में 'डिजिटल एजूकेशन' अथवा अध्ययन व अध्यापन की प्रक्रिया में 'ऑनलाइन प्लेटफार्म' के प्रयोग का चलन बढ़ा है किन्तु अभी कुछ समय पूर्व तक यह केवल उच्च स्तरीय शिक्षा, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के क्षेत्र में अथवा फिर समृद्ध परिवारों तक ही इसकी पहुँच थी किन्तु आज कोविड–19 महामारी के दौर में पूरी पढ़ाई ऑनलाइन प्लेटफार्म अथवा डिजिटल माध्यम जैसे Zoom App, HANGOUT, Facebook, Youtube आदि जैसे प्लेटफार्म पर आश्रित हो गयी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कुछ अति आवश्यक साक्षात्कार एवं पी0एच0डी0 हेतु आवश्यक साक्षात्कार आदि ऑनलाइन माध्यम से कराये जाने को मंजूरी दे दी है। आज सेमीनार की जगह वेबिनार के रूप में ऑनलाइन कांफ्रेंस की बहुलता सी आ गयी है। यह भी सम्भव है कि आने वाले समय में 'ऑनलाइन अथवा डिजिटल प्लेटफार्म' आधारित युनिवर्सिटी एवं कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थायें भी स्थापित किये जा सकते हैं। कोविड–19 महामारी के समय में अनवरत शिक्षा की कड़ी भी न टूटे और इस महामारी से बचाव के सर्वप्रमुख आधार अर्थात् Social Distancing/Physical Distancing को बनाये रखा जा सके, इस आशय से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने 'सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' (एन0एम0ई0आई0सी0टी0) के तहत National Digital Library of India (NDLI) का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के अतिरिक्त बांग्ला, आसामी, गुजराती सहित कुल 11 भाषाओं (हिन्दी और अंग्रेजी + 9 भाषाएं) में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व शोध कार्यों से जुड़े संसाधन एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु सराहनीय कार्य किया गया है। इसे आरम्भ किये जाने के उद्देश्य के संदर्भ में कहा गया है "It is designed to provide support for all academic levels including researchers and life long learners, all disciplines, all popular forms of access devices and differently-abled learners."

कोविड–19 महामारी के इस दौर में 'डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम' अत्यधिक प्रभावी एवं सहायक सिद्ध हो सकता है, जिसका शुभारम्भ 1 जुलाई सन् 2015 को किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता युक्त इण्टरनेट नेटवर्क से सम्बद्ध कर देश में डिजिटल साक्षरता में सुधार लाना व उसे अधिक समृद्ध करना है। विदित है कि अभियान के तीन प्रमुख स्तम्भों में 'डिजिटल साक्षरता' एक प्रमुख स्तम्भ है। ध्यातव्य है कि इस अभियान के माध्यम से भारतनेट, डिजी लॉकर, ई–शिक्षा आदि जैसी सेवायें उपलब्ध करायें जाने का लक्ष्य रखा गया। इस हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कुल 2351.38 करोड़ रूपये के लक्षित व्यय के साथ लगभग 6 करोड़ ग्रामीण लोगों को अर्थात् लगभग 40 फीसदी ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता मुहिम में

सम्मिलित किये जाने की पहल की गयी है। किन्तु वर्तमान में जब अभियान प्रारम्भ किये लगभग 5 वर्ष पूरे होने को हैं, यह अभियान अपनी उस चरम परिणति पर नहीं है कि सिर्फ इसी एक अभियान के आधार पर हम ऑनलाइन डिज़िटल प्लेटफार्म को अपनी शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख आधार बना दें।

आज कतिपय अपवादों के साथ लगभग सभी विश्वविद्यालय ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से सिलेबस समाप्त किये जाने एवं घर रह कर शिक्षा की अनवरत प्रक्रिया को बनाये रखने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की अनियमितता उत्पन्न न हो।

निःसंदेह निकट भविष्य में ऑनलाइन अथवा डिजिटल प्लेटफार्म शिक्षा का एक अच्छा माध्यम सिद्ध हो सकता है किन्तु इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता कि 'यह उस आग की तरह है जहाँ एक ओर यह अच्छा भोजन पका सकती है तो वहीं दूसरी ओर यह घर को जला भी सकती है।' अतएव इसे व्यापक रूप से प्रचलन में लाने के पूर्व इसके सकारात्मक व नकारात्मक परिणामों का आकलन कर लेना चाहिए। आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में डिज़िटल प्लेटफार्म के प्रयोग के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ हैं, जो निम्नलिखित हैं:–

प्रमुख चुनौतियाँ

- ऑनलाइन अथवा डिजिटल माध्यम से अध्ययन व अध्यापन हेतु प्रत्येक छात्र के पास मल्टीमीडिया मोबाइल, लैपटॉप या कम्प्यूटर होने के साथ–साथ प्रिन्टर की उपलब्धता आवश्यक है जो कि स्वयं में एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त यदि यह उपलब्ध हो भी जाए तो इस बात की क्या गारण्टी है कि इसका इस्तेमाल अन्य गैर सरकारी कार्यों व गैर जरूरी कार्यों में न हो।
- यदि मोबाइल अथवा लैपटॉप उपलब्ध करा भी दिये जाए तो भारतीय परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता युक्त व हाई–स्पीड नेटवर्क की उपलब्धता आज भी सर्वत्र सम्भव नहीं है।
- यद्यपि 'सौभाग्य योजना' के तहत लगभग 99.9 प्रतिशत घरों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है तथापि कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट की उपलब्धता का स्तर चिन्ताजनक है। National Sample Survey 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ इण्टरनेट की उपलब्धता 14.9 प्रतिशत परिवारों तक है तो वहीं कम्प्यूटर की उपलब्धता मात्र 4.4 प्रतिशत परिवारों तक सीमित है। शहरी क्षेत्रों में 42 प्रतिशत परिवारों में इण्टरनेट तथा 23.4 प्रतिशत परिवारों में कम्प्यूटर उपलब्ध है जो कि ऑनलाइन शिक्षा हेतु किसी भी दृष्टि से पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।
- वर्तमान में जब समूचा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है तो ऐसे में प्रत्येक छात्र से यह उम्मीद करना बेमानी होगी कि उनके पास ऑनलाइन प्लेटफार्म हेतु आवश्यक संसाधन की व्यवस्था करने तथा मंहगे रिचार्ज हेतु पैसे उपलब्ध हों जबकि भारत की लगभग एक चौथाई जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
- एक बेहतर शिक्षा हेतु शिक्षक एवं छात्र के मध्य बेहतर सह–सम्बंधों एवं सुगम संचारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है किन्तु ऑनलाइन प्लेटफार्म पर इसका पूर्णतः अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक छात्र किसी मुद्दे पर किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले 'संदेह' पर प्रश्न पूंछने तथा शिक्षक द्वारा सम्बद्ध संदेह के समाधान किये जाने की प्रक्रिया अत्यन्त मुश्किलों भरी होगी।
- यह उम्मीद किया जाना समीचीन नहीं होगा कि शिक्षक एवं छात्र दोनों ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी टेक्नोलॉजी से पूर्णतः परिचित हों।
- परीक्षा एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हो जाएगी। क्या परीक्षा घर बैठे होगी अथवा किसी संस्था में? निबन्धात्मक स्वरुप की परीक्षाओं का क्या होगा? क्योंकि आज Social Distancing के नियमों का पूर्णतः पालन किये जाने की स्थिति में कई कॉलेज परीक्षा सम्पन्न कराये जाने में असमर्थता व्यक्त कर चुके हैं। यह समस्या उन संस्थाओं के लिए और अधिक विकट होगी जहाँ सेमेस्टर व्यवस्था लागू है।
- यदि ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर भी दिया जाए तो पारिवारिक अथवा घरेलू माहौल में अनुशासनबद्ध तरीके से 5 से 6 घण्टे एक साथ बैठने की अपेक्षा एक बच्चे से नहीं की जा सकती। इन स्थिति में औपचारिक शिक्षा की दृष्टि से यह अधिक मुश्किल भरा पक्ष हो सकता है।

आगे की राह

विगत दिनों में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज प्रारम्भ करने को लेकर कहा था कि– "Online education is being taken up in a big way. Another 12 channels will be added. It will be great help to students in rural areas. Children love technology and adapt quickly. Top 100 universities will be allowed to start online courses by May 30." इतना ही नही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'एकल खिड़की' पर आधारित व्यवस्था के रूप में National Digital Library of India का प्रारम्भ किया गया ही है। इसके अतिरिक्त SWAYAM Online Course, CEC-UGC Youtube Channel, Free and Open Source Software for Education (FOSSEE), Google Classroom, The National Programme on Technology Enhanced Learning (NEPTL) आदि निकट भविष्य में ऑनलाइन शिक्षा के बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकते हैं। यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि विगत कुछ वर्षों से विभिन्न प्राइवेट कोचिंग संस्थानों द्वारा ऑनलाइन क्लॉसेज चलाये जाते रहे हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि लगभग पिछले एक दशक से उच्च शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन क्लासेज का प्रचलन है किन्तु इतने लम्बे समय से प्रचलन में रहने के बाद भी यह परम्परागत अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया को अभी तक चलन से बाहर नहीं कर सका है। आज भी 'क्लॉसरूम' आधारित 'सामूहिक शिक्षा' (Blended Learning) अध्ययन–अध्यापन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। अतः ऐसी स्थिति में किसी नयी व्यवस्था अथवा किसी नये माध्यम की ओर अचानक शिफ्ट कर जाना तर्कसंगत नहीं होगा।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहें तो कोविड–19 महामारी का भारतीय राजनीति एवं शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। जहाँ एक ओर 'सहयोगात्मक एवं सहकारी संघवाद' की भावना दिखी, असमान राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों के मध्य सहकार की भावना भी देखी गयी तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों का पलायन (मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन तथा अपने ही देश में मजदूरों को 'पर–प्रान्तीय' एवं 'प्रवासी' मजदूर कहा जाना अत्यन्त निराशाजनक होने के साथ–साथ चिन्ताजनक भी है), विभिन्न राजनीतिक दलों में असहयोग की स्थिति आदि का भी सामना करना पड़ा। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि महामारी से निपटने का दायित्व किसी सरकार अथवा राजनीतिक दल का ही नहीं अपितु हम सब का दायित्व है। अतएव हम सभी भारतीयों को एकजुटता एवं बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुये इस महामारी से निपटने में अपने दायित्व का निर्वहन करना है।

निकट भविष्य में न केवल भारतीय राजनीति व शिक्षा व्यवस्था पर बल्कि भारत के साथ–साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, विश्व व्यापार, अमरीका का विश्व महाशक्ति के रूप में

पराभव अथवा अमरीका की धूमिल होती वैश्विक छवि आदि समूचे विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने में सक्षम होगी। सारगर्भित रूप से कहें तो मानव सभ्यता का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो कोविड–19 महामारी के प्रभाव से अछूता रहे।

भारत में न केवल केंद्र व राज्य सरकारें बल्कि सरकार के तीनों स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित कर जनता को सहयोग एवं सुरक्षा का विश्वास दिलाना होगा जिससे इस महामारी के समाधान की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाया जा सके। शासन और प्रशासन के साथ–साथ हमें व्यक्तिगत स्तर पर इस महामारी के दौर को मानव सेवा एवं राष्ट्र सेवा के अवसर के रूप में लेते हुए अपने उत्तरदायित्व निर्वहन करना होगा। अतएव इस संकट की घड़ी में हमें व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये इस संकट को एक 'अवसर' के रुप में परिवर्तित करना होगा। एक ऐसा 'अवसर' जिसमें 'कर्त्तव्यनिष्ठा', 'दायित्व–बोध' एवं 'मानवता' के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन की भावना के साथ–साथ आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा निहित हो।

सन्दर्भ सूची

1. Dr. Ashwini Kumar Sharma. COVID-19 creating a paradigm shifts in India's Education System, Economic Times, 2020.
2. CP Gopinathan, Ramachandran K. Higher Education Post COVID-19, thehindu.com, 2020.
3. Joshi SK. Time for a New Paradigm of Swadeshi, Times of India, 2020.
4. www.ndl.gov.in
5. www.ndl.iitkgp.ac.in
6. www.mhrd.gov.in
7. Times of India
8. Economic and Political weekly. (www.epw.in)
9. जगमोहन सिंह राजपूतः गांधी को समझने का समय, जनसत्ता, 2 अक्टूबर, 2019
10. जनसत्ता
11. राष्ट्रीय सहारा